वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. आलप्पा) : (क) जी, हां।

(ख) जैसे कुछ राज्यों में योजना समाप्त कर दी गई हैं, मध्य प्रदेश को वर्ष 1997-98 के लिए कोई लक्ष्य आबंटित नहीं किए गये हैं।

Corruption in Apparel Export Promotion Council

2468. SYED SIBTEY RAZI: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether it has been reported that exporters of silk garments alleged that corruption in Apparel Export Promotion Council offices was hindering their export efforts;

(b) whether other tactics of corrupt practices by officials of AEPC havo also been explained to the Textile Secretary of Government;

(c) whether Government propose to take some action on these allegations of exporters; and

(d) if so, the details thereof; and if not, the reaSow: therefor?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI R. L. JALAPPA): (a) to (d1 la a Seminar held of NIPT Campus, New Delhi on July 23, 1997, some silk exporters co-mplained about alleged delays in certification of shipping documents for silk garments biy the Apparel Exptort Pfo-motion Council (AEPC). The AEPC has reported that no caSe has come to their notice recently where there has been any delay in certification of shipping documents f#t silk garment exports by them.

कपास उत्पादन

2469. **श्री गोपाल सिंह जी. सोलंकी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कपास उत्पादन राज्य और उनके द्वारा उत्पादित वर्ष-वार उत्पाद क्षमता का ब्यौरा क्या हैं;

(ख) क्या देश में कपास के उत्पादन में कुछ वर्षो से कमी आ रही हैं;

(ग) क्या किसानो को उनके उत्पादन का पर्याप्त समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा हैं;

(घ) 1993-94, 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान देश में प्रति हैक्टयेर कपास का उत्पादन कितना हुआ हैं;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान कपास की खेती के अन्तर्गत क्षेत्र का वर्ष-वार ब्यौरा क्या हैं; और

(च) क्या पिछले कुछ वर्षो में गुजरात में वर्षा की कमी और अन्य संसाधनो के अभाव के कारण कपास के उत्पादन में काफी कमी आयी हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) और (ख) पिछले तीन कपास मौसम के दौरान कपास के राज्यवार उत्पादन के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। (नीचे देखिए)

(ग) जी नहीं। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्यों का निर्धारण यह सुनिश्चित करने के लिए करती हैं कि किसानों को उनके उत्पाद के लिए लाभप्रद कीमतें प्राप्त हों। कपास की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफी ऊंची चल रही हैं।